भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 694
दिनांक 04 दिसंबर 2025

घरेलू एलपीजी के उपयोग में गिरावट

†694. **डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियनः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ऐसी रिपोर्टों की जानकारी है, जिनमें सब्सिडी सहायता में हाल ही में की गई कटौती के बाद घरेलू एलपीजी के उपयोग में कमी आने का संकेत दिया गया है और क्या लगभग तीन-चौथाई परिवार अभी भी प्राथमिक खाना पकाने के ईंधन के रूप में एलपीजी पर निर्भर हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय तथा तमिलनाडु में घरों में एल.पी.जी. की पहुंच तथा उसके रुझान के नवीनतम आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कम आय वाले शहरी और ग्रामीण परिवारों के लिए एलपीजी सिलेंडरों का सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए उज्ज्वला/लक्षित सब्सिडी तंत्र के अंतर्गत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन के पुनः उपयोग को रोकने के लिए कौन-से अन्य तरीके सुझाए गए हैं विशेषकर वहाँ जहाँ जलाने की लकड़ी महंगी है या नहीं मिलती है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से मई, 2016 में शुरू की गई थी। परिवारों द्वारा एलपीजी उपयोग में कोई कमी नहीं हुई है। सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप घरेलू एलपीजी की खपत लगातार बढ़ रही है। घरेलू एलपीजी की खपत सामूहिक स्तर पर वित्त वर्ष 2023-24 में 26207 एमएमटी से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 27654 एमएमटी हो गई है। परिवारों के स्तर पर भारत में घरेलू एलपीजी की प्रति व्यक्ति खपत (प्रति वर्ष लिए गए 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर के संदर्भ में) वित्त वर्ष 2023-24 में 5.78 से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 5.96 और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 6.05 हो गई है।

सरकार ने पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को और अधिक किफायती बनाने और उनके द्वारा एलपीजी का निरंतर उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मई 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर (और 5 किलोग्राम कनेक्शन के लिए आनुपातिक रूप से यथा आनुपातिक) पर 200 रुपये की निर्धारित राजसहायता शुरू की। अगस्त, 2023 में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं हेतु एलपीजी के मूल्यों में

200 रुपये तथा मार्च, 2024 में 100 रुपये की कमी की गई। सरकार ने अक्टूबर 2023 में निर्धारित राजसहायता को बढ़ाकर 300 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर (और 5 किलोग्राम कनेक्शन के लिए आनुपातिक रूप से यथा आनुपातिक) कर दिया। सरकार, वित्त वर्ष 2025-26 हेतु पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के 9 रिफिल (और 5 किलोग्राम कनेक्शन के लिए आनुपातिक रूप से यथा आनुपातिक) के लिए 300 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की निर्धारित राजसहायता प्रदान कर रही है।

इसके अलावा, जागरूकता पैदा करने और एलपीजी के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें अभियान चलाना, कनेक्शन का नामांकन और वितरण करने के लिए मेले/शिविर आयोजित करना, आउट ऑफ होम (ओओएच) होर्डिंग्स, रेडियो जिंगल्स, सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) वैन आदि के माध्यम से प्रचार करना, एलपीजी पंचायतों के माध्यम से अन्य पारंपरिक ईंधनों की तुलना में एलपीजी के उपयोग के लाभों तथा एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नामांकन/जागरूकता शिविर का आयोजन, पीएमयूवाई कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आधार नामांकन और बैंक खाते खोलने हेतु उपभोक्ताओं और उनके परिवारों को सुविधा प्रदान करना शामिल है। सरकार ने पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा एलपीजी की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें अग्रिम नकद व्यय को कम करने के लिए 14.2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक का स्वैप विकल्प, 5 किलोग्राम डबल बॉटल कनेक्शन का विकल्प, लाभार्थियों को निरंतर आधार पर एलपीजी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत का आयोजन, बड़े पैमाने पर जागरूकता शिविर आदि शामिल हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति व्यक्ति खपत (प्रति वर्ष लिए गए 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडरों की संख्या के संदर्भ में) 3.68 (वित्त वर्ष 2021-22) से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 4.47 हो गई है।

दिनांक 01.11.2025 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य की 1653 डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स सहित देश भर में कुल 25,587 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स हैं। इन्हें, तमिलनाडु की 19 डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स सहित देश भर में स्थित तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के 214 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट के माध्यम से सेवा प्रदान की जाती है। ओएमसीज द्वारा ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में एलपीजी की पहुंच में सुधार करने के उद्देश्य से देश भर में दिनांक 01.04.2016 से 31.10.2025 के दौरान, 8017 डिस्ट्रीब्यूटरशिप कमीशन की गई हैं, जिनमें से 7420 (अर्थात 93%) ग्रामीण क्षेत्रों को सेवा प्रदान कर रही हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, देश में एलपीजी की पहुँच अप्रैल 2016 में 62% से बढ़कर अब लगभग संतृप्ति की ओर है। इसी प्रकार से, तमिलनाडु में एलपीजी की पहुँच भी अप्रैल 2016 में 80.8% से बढ़कर अब लगभग संतृप्ति की ओर है।

*****